INTERNATIONAL RESEARCH JOURNAL OF HUMANITIES AND INTERDISCIPLINARY STUDIES
(Peer-reviewed, Refereed, Indexed & Open Access Journal)
DOI : 03.2021-11278686 ISSN : 2582-8568 IMPACT FACTOR : 5.828 (SJIF 2022)

आगरा मण्डल के कृषि विकास में जिला सहकारी बैंको की भूमिका

(आठवी व नवीं पंचवर्षीय योजना के सन्दर्भ में)

(The Role of Co-operative Banks in the Development of Agriculture in Agra Region)

डॉ. पुष्पेन्द्र कुमार शर्मा
सहायक प्रोफेसर
विवेकानन्द कॉलेज आफ एजुकेशन, अलीगढ

DOI No. 03.2021-11278686 **DOI Link ::** https://doi-ds.org/doilink/08.2022-56136124/IRJHIS2208003

प्रस्तावना :

सहकारिता आन्दोलनों का अध्ययन करने पर ज्ञात होता है कि कुछ विकसित देशों को छोडकर प्रारम्भ में विकाशील देशों के सहकारिता आन्दोलनों को किसी प्रकार का सरकारी संरक्षण नहीं मिला भारत में सहकारी आन्दोलन का आरम्भ एवं विकास प्रारम्भ से ही सरकारी अधिनियमों के अन्तर्गत हुआ है। देश के सम्पूर्ण सहकारी आन्दोलन का मूलस्वरूप कृषि साख सहकारिता से सम्बन्धित रहा है भारत में सहकारी बैंक व्यवस्था का ढाचा एक पिरामिड के समान है जो संघीय व्यवस्था पर आधारित है सम्पूर्ण ढांचे का आधार ग्राम स्तर पर स्थापित प्राथमिक साख समिति है जिस पर सम्पूर्ण सहकारी बैंक व्यवस्था संगठित की गई है। प्राथमिक साख समितियों को मिलाकर जिला स्तर पर केन्द्रीय समिति संगठित की जाती है जिससे समितियॉ संघीय व्यवस्था के अनुसार सदस्य के रूप में सम्बन्धित रहती है जिला स्तर पर स्थापित केन्द्रीय समिति को ही केन्द्रीय सहकारी समिति कहते हैं। राज्य स्तर पर भी केन्द्रीय सहकारी बैंकों की भी एक संघीय संस्था स्थापित की जाती है जिसे सर्वोच्च या शिखर बैंक अथवा राज्य सहकारी बैंक कहते है। साख व्यवस्था को नीचे दिये गये वर्गीकरण के आधार पर प्रस्तुत किया गया है।

राज्य स्तरीय सहकारी बैंक

↓

जिला स्तरीय केन्द्रीय सहकारी बैंक

↓

प्राथमिक साख समिति

उपरोक्त सहकारी बैंक व्यवस्था के ढांचे को देखने पर यह ज्ञात होता है कि विभिन्न स्तरों पर स्थापित संस्थायें एक दूसरे से सम्बन्ध है। वास्तविकता यह है कि वैधानिक तथा वित्तीय मामलों में उनका अलग–अलग अस्तित्व है प्रत्येक संस्था अपने स्तर तथा क्षेत्र में कुछ विशेष उददेश्यों की पूर्ति करती है जिसके कारण उसे एक स्वतंत्र इकाई माना जाता है। सामूहिक रूप से यह सभी संस्थायें एक ऐसे संगठन का निर्माण करती है जो

पारस्परिक सहायता करने तथा सहायक आन्दोलन में सन्तुलन बनाने के उद्देश्य से बाहरी स्त्रोत से ऋण प्राप्त करती हैं। प्राप्त किये गये ऋण के उचित प्रयोग की वह जॉच करती है तथा देय तिथियों पर उन ऋणों को वसूल करने की व्यवस्था करती हैं संघीय ढांचे की विशेषता यह है कि स्वंत्रत होते हुये भी विभिन्न संस्थाओं की सम्पूर्ण कड़ी अपनी प्रत्येक इकाई से प्रभावित होती है।

मण्डल में प्रारम्भिक कृषि सहकारी समितियों की प्रगति निम्न प्रकार रही है।

वर्ष	समिति संख्या	व समितियों के अन्तर्गत ग्राम
1992–93	594	6609
1993–94	627	6610
1994–95	626	6604
1995–96	626	6604
1996–97	627	6602
1997–98	640	6612
1998–99	630	6599
1999–00	630	6599
2000–01	629	6596
2001–02	629	6596

स्त्रोत– सांख्यिकी पत्रिका आगरा मंण्डल वर्ष 1994, 96, 98, 2000, 02 पृष्ठ 8

विकास परक योजनाओं में सहकारी बैंकों के विकास को देखा जाये तो सहकारिता के आन्दोलन के विकास की इस मंजिल में उत्तर प्रदेश में सहकारी बैंको के विकास का क्रम भी शामिल है। विश्व में चल रहे सहकारी आन्दोलन क्रमिक विकास उत्तर प्रदेश की अर्थ व्यवस्था को भी अछूता न रख सका। अतः उत्तर प्रदेश में जमीदारों के शोषण से मुक्ति दिलाने और कृषि विकास क्षेत्र में आने वाली वित्तीय समस्याओं के निराकरण करने के लिये 1906 में प्रथम सहकारी बैंक की स्थापना की गई। धीरे–धीरे इस बैंक के लिये निर्धारित किये गये उदेश्यों के अनुरूप इसकी शाखाओं का विस्तार किया गया प्रदेश में इस समय एक राज्य सहकारी बैंक, 60 जिला सहकारी बैंक और ग्रामीण स्तर पर 8599 प्राथमिक कृषि साख समितियॉ कार्य कर रही हैं।

उत्तर प्रदेश में किसानों को विचौलियो तथा आढतियों के शोषण से बचाने में सहकारी क्षेत्र की क्रय–विक्रय समितियों की भूमिका महत्वपूर्ण सिद्ध हुई है उत्तर प्रदेश में जिला स्तर पर 60 सहकारी संघ तथा तहसील स्तर पर 268 क्रय–विक्रय सहकारी समितिया कार्यरत है जो कृषि ऊपज का विपणन करती है।

मण्डल में कृषि नवीनकरण की प्रक्रियाओं के साथ–साथ रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग भी कृषि क्षेत्र में भी बढ़ता गया है जिसका प्रभाव खेती की प्रति हेक्टेयर उत्पादक पर पड़ा है। कृषि विकास तथा फसलो की अधिक ऊपज का बहुत कुछ आधुनिक तकनीक के प्रयोग पर निर्भर करता है इस सम्बन्ध में सहकारी बैंकों की भूमिका बहुत ही महत्वपूर्ण रही है।

वर्ष 2001–02 में मण्डल में जितने उर्वरकों का प्रयोग किया उसमें नाइट्रोजन 192430 मीट्रिक टन, फॉस्फोरस 97870 मीट्रिक टन एवं पोटाश 7652 मीट्रिक टन प्रयोग किया गया। मण्डल में कृषि उर्वरकों का

विभिन्न वर्षो में उपयोग निम्न तालिका से स्पष्ट है।

मण्डल में कृषि उर्वरक का विवरण (मी. टन)

वर्ष	नाइट्रोजन	फॉस्फोरस	पोटाश
1992–93	128589	39379	1624
1993–94	158611	45570	1822
1994–95	178859	60087	6248
1995–96	187865	65647	5964
1996–97	194760	68484	5683
1997–98	200530	74189	5979
1998–99	210793	67835	6573
1999–00	211770	100993	8411
2000–01	188580	85917	7124
2001–02	192430	97870	7652

स्त्रोत– सांख्यिकी पत्रिका आगरा मण्डल वर्ष 94, 96, 98, 2000, 2002

मण्डल में बीज वितरण में सहकारी बैंको की प्रमुख भूमिका रही है क्योंकि गेहूँ आगरा मण्डल का प्रमुख कृषि उत्पाद है अतः प्रत्येक वर्ष रवी अभियान के अन्तर्गत गेहूँ के उन्नतशील बीज का वितरण किया जाता है मण्डल में जनपदवार बीज वितरण की स्थिति निम्न प्रकार रही है।

जनपद का नाम	**बीज वितरण (कुन्तल में)**
अलीगढ	18150
आगरा	21574
एटा	21900
फिरोजाबाद	15729
मथुरा	30878
महामायानगर	30878
मैनपुरी	21050

स्त्रोत– सामाजिक आर्थिक समीक्षा आगरा मण्डल वर्ष 2001–02

निष्कर्ष :

हम जानते हैं सहकारिता शब्द दो शब्दों सह + कार से मिलकर बना है जिसमें 'सह' का अर्थ मिलकर 'कार' का कार्य से है अतः सहकारिता का अर्थ मिलकर कार्य करने से आगरा मण्डल जो कि एक उत्तर प्रदेश का एक कृषि प्रधान मण्डल है सहकारी बैंको के माध्यम से इस मण्डल का तीव्र गति से विकास हुआ है किसान आत्मनिर्भर बन रहे है लेकिन इसे और तेज करने की आवश्यकता है।

संदर्भ ग्रन्थ सूची :

1. सांख्यिकी पत्रिका आगरा मण्डल 194, 96, 98, 2000, 02
2. सामाजिक आर्थिक समीक्षा आगरा मण्डल – 2001–02
3. प्रतियोगिता दर्पण मार्च 1999, जुलाई 2002, मार्च 2003
4. द कोअपरेटर– नई दिल्ली मार्च 2004
5. उत्तर प्रदेश – 2003
6. आर्थिक सर्वेक्षण – 1992–93, 1998–99, 2001–02
7. दैनिक जागरण आगरा